<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय ,नैनीताल</u>

फौजदारी अपील संख्या 532 /2013

सोनिया. .....अपीलार्थी

बनाम

नितिन सैनी एवं अन्य। ... ... उत्तरदाता

सरकारी अपील संख्या नंबर 14, 2014

उत्तराखंड राज्य. .....अपीलार्थी

बनाम

नितिन सैनी. .....प्रतिवादी

उपस्थितः

श्री देवेश बिश्नोई, अपीलकर्ता के लिए न्याय मित्र।
श्री जे.एस विर्क, श्री राकेश कुमार जोशी के साथ उप महाधिवक्ता, राज्य के लिए ब्रीफ होल्डर।
सुश्री श्रुति जोशी, प्रतिवादी के लिए माननीय एमिकस क्यूरी।

<u>सुनवाई और निर्णय की तिथि: 10.05.2022</u>

कोरम: -
श्री संजय कुमार मिश्रा, एसीजे।
श्री रमेश चंद्र खुल्बे, जे

पक्षकारों के अधिवक्ताओ को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-
(श्री, एस.के. मिश्रा, एसीजे)

1. ये दो अपील बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, एक पीड़ित लड़की (नाम रोक दिया गया) द्वारा अधिमानित की गई है और दूसरी उत्तराखंड राज्य द्वारा अधिमानित की गई है। अपीलकर्ताओं ने 2012 के सत्र परीक्षण संख्या 150 में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रुड़की, जिला-हरिद्वार द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.10.2013 को चुनौती दी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 376 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपों से प्रतिवादी को बरी किया गया था। दंड संहिता, 1860 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "दंड संहिता" के रूप में संदर्भित)।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनांक 07.03.2012 को प्रातः लगभग 8:30 बजे अभियोक्त्री थाना-गंगनहर, जिला-हरिद्वार थाना-गंगनहर के समक्ष उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। इस आशय से कि वह 2010 से प्रतिवादी-नितिन सैनी से परिचित थी, जिसका मोबाइल नंबर 9058546051 है। उसने आगे कहा कि वह शादी के लिए झूठा आश्वासन देकर उसके साथ अवैध संबंध बना रहा था। हालांकि, पीड़िता इस तरह के रिश्ते से व्यथित थी, उसने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया लेकिन इस तरह के रिश्ते के दो साल बाद, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। मजबूरी में, क्योंकि प्रतिवादी ने अपना वादा पूरा नहीं किया जो उसने उससे किया था। उसने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से, यह भी स्पष्ट है कि वे पतंजलि योगपीठ के बाहर मिले थे जहाँ वह इलाज कराने जा रही थी और प्रतिवादी वहाँ काम कर रही थी।

3. इस तरह की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर, एक मामला अपराध सं. दंड संहिता की धारा 420, 376 और 506 के तहत 2012 के 96 एस.एच.ओ. द्वारा शुरू किया गया था। थाना-गंगनहर, रुड़की एवं मामले की जांच की गयी जांच के क्रम में, जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की जांच की। जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता/अभियोजिका का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। जांच पूरी होने के बाद, उसने उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जांच के दौरान, क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित लड़की का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने इनकार की दलील दी।

4. अपने मामले को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीड़िता-अभियोजन पक्ष सहित पांच गवाहों की जांच की क्योंकि PW1, PW2 उसके पिता हैं (नाम रोक दिया गया है), PW3 कांस्टेबल आनंद पाल सिंह ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की है, PW4 डॉ. दीपा ने चिकित्सकीय जांच की है पुलिस द्वारा मांग पर अभियोजन पक्ष; PW5 सब इंस्पेक्टर निर्मला भट्ट मामले की जांच अधिकारी हैं। इन पांच गवाहों के परीक्षण के अलावा अभियोजन पक्ष ने सात साक्ष्यों पर भी भरोसा किया है। अपने मामले की पैरवी करने के लिए बचाव पक्ष ने न तो कोई गवाह पेश किया और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया।

5. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को ध्यान में रखने के बाद और मुख्य रूप से इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि घटना के समय अभियोजिका बालिग थी, जैसा कि PW4 डॉ. दीपा द्वारा किए गए परीक्षण और समय का उल्लेख न करने जैसी अन्य परिस्थितियों द्वारा स्थापित किया गया था, घटना की तारीख और महीना और देर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना; प्रतिवादी के सेल फोन नंबर के बारे में गलत बयान, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। प्रतिवादी की बरी करने के ऐसे आदेश को दोनों अपीलों में चुनौती दी जाती है।

6. श्री दवेश बिश्नोई, माननीय एमिकस क्यूरी, अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता की ओर से पेश होकर यह तर्क देंगे कि चूंकि अभियोजिका ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा था कि उसने अधिनियम के समय सहमति नहीं दी थी और उसकी सहमति गलत धारणा से प्राप्त की गई थी , माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया है, रिकॉर्ड पर एक त्रुटि की है।

7. श्री जे.एस. विर्क, माननीय उप महाधिवक्ता भी अभियोजिका की ओर से पेश होने वाले माननीय एमिकस क्यूरी का समर्थन करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि पीड़ित लड़की ने घटना के बारे में बयान दिया है, इसलिए माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर से उसके संस्करण पर अविश्वास करना और बरी करना उचित नहीं था| प्रतिवादी।

8. सुश्री श्रुति जोशी, विद्वान एमिकस क्यूरी, दोनों मामलों में प्रतिवादी की ओर से पेश होकर तर्क देंगी कि यह दोषमुक्ति के फैसले को पलटने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी और पर्याप्त परिस्थिति नहीं है। वह "प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2019) 9 SCC 608" के मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी द्वारा उससे शादी करने के वादे के बारे में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए तथ्य की गलत धारणा को स्थापित करना होगा। शुरू से ही, प्रतिवादी, जिसने कथित रूप से अभियोजिका को शादी करने का वादा किया था, का विवाह करने का कोई इरादा नहीं था और प्रतिवादी द्वारा इस तरह के आश्वासन पर अभियोक्त्री ने संभोग के लिए सहमति दी। वह इस न्यायालय का ध्यान पैरा नं.35 आक्षेपित निर्णय जिसमें माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन कारण देते हुए उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा। इस प्रकार, पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने पर, इस न्यायालय का मत है कि इस मामले में निर्णय के लिए निम्नलिखित दो आवश्यक प्रश्न उठते हैं: -

"(i). क्या प्रतिवादी ने बिना किसी इरादे के शादी करने का झूठा आश्वासन देकर अभियोजिका के साथ यौन संबंध बनाए थे?

(ii). क्या शादी का वादा करने और फिर अभियोजिका के साथ यौन संबंध बनाने की प्रतिवादी की हरकतें बलात्कार की श्रेणी में आती हैं?"

9. पहले प्रश्न पर आते हैं, यह देखा गया है कि इस मामले में अभियोजिका का PW1 के रूप में परीक्षण किया गया है। उसने कहा है कि उसके और प्रतिवादी के बीच अंतरंगता विकसित हुई, क्योंकि वह पतंजलि योग पीठ जा रही थी, जहां वह अपना इलाज करा रही थी और प्रतिवादी वहां काम कर रही थी। ऐसे रिश्ते के दौरान दोनों ने पतंजलि योग पीठ के सामने स्थित एक होटल में शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, ऐसे होटल के रजिस्टर में, उनके होटल में रहने के बारे में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है और अभियोजिका के बयान के संबंध में कोई पुष्टि करने वाला साक्ष्य नहीं है।

10. रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि अभियोजिका ने ऐसी घटना की किसी विशिष्ट तिथि, समय और महीने का उल्लेख नहीं किया है जब उसने प्रतिवादी के साथ संभोग किया था। उसने आरोप लगाया कि इस गलत धारणा के तहत कि प्रतिवादी भविष्य में उससे शादी करेगा, उसने प्रतिवादी के साथ यौन संबंध बनाने की सहमति दी। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निर्णय के पैराग्राफ 35 में मामले के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से अभियोक्ता के साक्ष्य के संबंध में बहुत विस्तृत रूप से निपटाया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोक्त्री का साक्ष्य संदिग्ध है और स्पष्ट नहीं है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आगे पाया कि यदि अभियोजिका का प्रतिवादी के साथ कोई यौन संबंध भी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसकी अपनी सहमति से था। उसने अभियोजिका के इस कथन पर भी विश्वास नहीं किया कि प्रतिवादी ने विवाह के झूठे वादे के साथ उसकी सहमति प्राप्त की थी।

11. पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों की सराहना करने के लिए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **घूरे लाल बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (2008)10 SCC 450** के मामले में ट्रायल कोर्ट की बरी होने को खारिज करने या अन्यथा परेशान करने के लिए निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करते हैं। ऊपर। (2008) 10 एससीसी 450. घूरे लाल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के मामले में अपीलीय अदालत की क्वेरी के दायरे से निपटा है और निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया है:

"70. xxxx

ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जिनमें अपीलीय अदालत के पास ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करने के लिए "बहुत ही पर्याप्त और सम्मोहक कारण" होंगे। "बहुत महत्वपूर्ण और सम्मोहक कारण" तब मौजूद होते हैं जब:

(i) तथ्यों के संबंध में निचली अदालत का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है;

(ii) ट्रायल कोर्ट का निर्णय कानून के गलत दृष्टिकोण पर आधारित था;

(iii) ट्रायल कोर्ट के फैसले के परिणामस्वरूप " घोर न्याय-हत्या " होने की संभावना है;

(iv) साक्ष्य से ट्रायल कोर्ट का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था;

(v) ट्रायल कोर्ट का फैसला स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित था;
(vi) ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की अनदेखी की है या भौतिक साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ा है या मरने वाले बयानों/बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट आदि जैसे भौतिक दस्तावेजों की अनदेखी की है।

vii) यह सूची व्याख्यात्मक है, संपूर्ण नहीं।

12. विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के मामले में अपराध में दोषसिद्ध अभियुक्तों की बेगुनाही की धारणा और मजबूत हो जाती है। अपीलीय अदालत को विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके लिए बाध्यकारी और पर्याप्त कारण न हों। यह पता लगाने के लिए कि क्या तथ्यों के निष्कर्षों को पलटने के लिए मजबूर करने वाले कारण हैं, तो न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि क्या विद्वान विचारण न्यायाधीश ने किसी साक्ष्य की अनदेखी की है; क्या विचारण न्यायाधीश ने सबसे अनुचित तरीके से साक्ष्य की व्याख्या करने में गलती की है जिसे विकृत कहा जा सकता है; क्या विचारण न्यायाधीश के निर्णय से न्याय के निष्फल होने की संभावना है।

13. इस मामले में, न तो श्री दवेश बिश्नोई और न ही श्री जे.एस. विर्क, माननीय उप महाधिवक्ता मामले के किसी भी पहलू को इंगित कर सकते हैं, जो वर्तमान मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के दायरे में लाएगा। घुरे लाल (सुप्रा) की। इस प्रकार, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहाँ हमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को पलट देना चाहिए। हमारी राय है कि विद्वान

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने किसी भी साक्ष्य की सराहना करते हुए उसकी उपेक्षा नहीं की। वास्तव में, उसने उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा है जो उसके सामने शपथ पर कहे गए हैं और सबूतों की सराहना करते हुए फैसले में चर्चा की गई है। साक्ष्य की प्रशंसा को विकृत या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, ट्रायल जज द्वारा रिकॉर्ड किए गए तथ्य के निष्कर्ष को पलटने के लिए कोई पर्याप्त और बाध्यकारी कारण नहीं है।

14. अगला सवाल शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने की सहमति का है| इस संबंध में, हम प्रमोद सूर्यभान पवार (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए अनुपात पर ध्यान देते हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निर्माता द्वारा समझ पर दिए गए झूठे वादे के बीच अंतर है। कि यह टूट जाएगा, और वादे का उल्लंघन होगा, जो अच्छे विश्वास में किया गया था लेकिन बाद में पूरा नहीं हुआ। **अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 13 SCC 1** के मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए।, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि उपरोक्त निर्णयों का योग और सार यह होगा कि यदि यह स्थापित हो जाता है और साबित हो जाता है कि शुरुआत से ही अभियुक्त जिसने अभियोजिका ने विवाह का वादा किया था, विवाह करने का कोई इरादा नहीं था और अभियोजिका ने अभियुक्त द्वारा इस तरह के आश्वासन पर कि वह उससे शादी करेगा, संभोग के लिए सहमति दी, इस तरह की सहमति को तथ्य की गलत धारणा पर प्राप्त सहमति कहा जा सकता है, अनुसार दंड संहिता की धारा 90 और, ऐसे मामले में इस तरह की सहमति अपराधी को क्षमा नहीं करेगे और ऐसे अपराधी को दंड संहिता की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के रूप में कहा जा सकता है और अपराध के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। दंड संहिता की धारा 376।

15. **दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 SCC 675** जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि एक वादे के उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच अंतर है। इस प्रकार, न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रारंभिक चरण में शादी का झूठा वादा किया गया था। प्रमोद सूर्यभान पवार (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहां शादी करने का वादा झूठा है और वादा करते समय निर्माता का इरादा खुद इसका पालन करना नहीं बल्कि महिला को धोखा देना था उसे यौन संबंधों में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए, एक "तथ्य की गलत

धारणा" है जो महिला की "सहमति" को खत्म कर देती है। दूसरी ओर, वचन भंग को झूठा वचन नहीं कहा जा सकता। झूठे वादे को स्थापित करने के लिए, वादा करने वाले को देने के समय अपने वचन को बनाए रखने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए था। धारा 375 के तहत एक महिला की "सहमति" एक "तथ्य की गलत धारणा" के आधार पर दूषित होती है, जहां इस तरह की गलत धारणा उसके द्वारा उक्त अधिनियम में शामिल होने का चयन करने का आधार थी।

16. देर से, सोनू उर्फ **सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 SSC Online SC 181,** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। धारा 482 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न संहिता के, पूर्वोक्त सिद्धांतों को दोहराया है।

17. मौजूदा मामले में उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम देखते हैं कि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि शुरू से ही, प्रतिवादी का अपना वादा नहीं निभाने का कोई इरादा था जो उसने कथित रूप से किया था। बल्कि अभियोजिका ने जो एकमात्र बयान दिया है वह यह है कि उन्होंने एक होटल में संभोग किया और संभोग करने के बाद जब वह रोने लगी तो प्रतिवादी ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और फिर, उसने उससे शादी करने का वादा किया।

18. हमारी राय है कि रिकॉर्ड पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा अभियोजिका से किया गया कथित वादा इसे न रखने के इरादे से किया गया था और केवल यौन गतिविधि के लिए अभियोजिका की सहमति प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच दो साल से अधिक समय से संबंध चल रहे थे और उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

19. उपरोक्त परिदृश्य में, हमारा विचार है कि यह मानने के लिए यह एक उपयुक्त मामला नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। परिणामतः दोनों अपीलें आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं।

20. रजिस्ट्री को विचारण न्यायालय अभिलेख वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(रमेश चंद्र खुल्बे जे.) (संजय कुमार मिश्रा)
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश।